



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2022—वैशाख 23, शक 1944

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2022

क्रमांक एफ 13-01/2022/57-2 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल को और अधिक उपयोगी और सक्रिय किये जाने के परिपालन में नवीन स्वरोजगार योजनाओं के संचालन का निर्णय लिया गया है जिसके तहत राज्य शासन, एतदद्वारा, निम्न नवीन नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

संत रविदास स्वरोजगार योजना

योजना का लाभ - केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को निम्नानुसार अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधित प्रावधान होंगे:-

1- परियोजना सीमा : (अ) उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिए राशि रु. 1 लाख से रु. 50 लाख तक की परियोजनाएँ।

(ब) सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु रु 1 लाख से रु. 25 लाख तक की परियोजनाएँ।

2- प्राप्तता :

(क) आयु 18 - 40 वर्ष

(ख) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ग) आय सीमा: (अ) परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो। (ब) परिवार से आशय: (i) आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा (ii) आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है।

(घ) अन्य : (अ) आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे - MFI/ NBFC/SFB/PACS इत्यादि का डिफाल्टर ना हो। (ब) आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगर योजना का हितग्राही न हो।

3- वित्तीय सहायता : (1) ब्याज अनुदान : योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा।

(2) गारंटी फीस : म.प्र.शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।

4-प्रशिक्षण : योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

5-पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।

6-पात्र बैंक : पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में पंजीकृत MLI(Member Lending Institution) है।

7-योजना का क्रियान्वयन : इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल होगा। जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना का संचालन/समन्वय कराया जावेगा। योजनान्तर्गत जिला स्तर पर विभिन्न स्वरोजगर मूलक कार्यों से जुड़े विभागों- सूखम, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोदयोग विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा।

2) म.प्र.शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अपने विभागीय बजट में इस योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जायेगा। संत रविदास स्वरोजगर योजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट अनुसार जिलेवार एवं बैंकवार वित्तीय लक्ष्य (ब्याज अनुदान वितरण) निर्धारित किये जायेंगे।

3) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

4) योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए निर्धारित पोर्टल में ही अनुसूचित जाति वर्ग हेतु संत रविदास स्वरोजगर योजना के नाम से संचालन होगा जो कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से समन्वित होगा। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अन्तर्गत आवेदन करने पर भी उसे इस योजना अन्तर्गत पात्रता की स्थिति में लाभ प्राप्त होगा।

संत रविदास स्वरोजगार योजना

- **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- **योजना का क्रियान्वयन:** संत रविदास स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।
- **पात्रता:**
 - योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात् योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
 - आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
 - आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंगी करना होगा)।
 - आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
 - किसी भी राशीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
 - यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
 - सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
 - योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
- **वित्तीय सहायता:**
 - उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाएं
 - सेवा (सर्विस) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाएं
 - ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा